cine. In the First Plan, the total allocation was Rs. 40 lakhs only. Now, Sir, it is hundred times more or Rs. 40 crores for the ISM in the Central sector.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : थर्ड डाक्टर का क्या किया है ?

SHRI KRISHNA KUMAR: Sir, the Government order on the posting of the third doctor from among the ISM disciplines in the Primary Health Centres in the country is still extant. Some of the States have implemented it and some of the States have not implemented it. We are steadily pursuing the matter with the States. This is a State subject. We are trying to implement it.

श्री बापू कालदाते : सभापति महोदय, अब यह बात सब लोग मान रहे हैं कि माडर्न मेडिसिन में बहुत सारे साईड इफैक्टस होते हैं।

इसके दो कारण है, एक तो बगैर जाने हुए कोई भी बीमारी हो जाए, तो ब्राड स्प्रेक्टम एंटिबायटिक्स जिसका कुछ असर होता है, इसको न देखते हुए भी इन दवाइयों का इस्तेमाल इस देश में होता है और लोग इस बात पर आ चुके हैं कि अगर ठीक ढंग से सोचें तो जो आयुर्वेद या जो हिंदुस्तानी, भारतीय पद्धति है, उसका उपयोग बगैर साईड इफैक्टस के किया जा सकता है ।

इसके लिए सरकार का ध्यान इस तरफ अगर गया हो कि जितने इस पद्धति को विकसित करना चाहिए एक तरफ से ।

दूसरी तरफ हम देखते है कि राज्यों में—जिस राज्य से मैं खुद आता हूं, उस राज्य में जहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर्ज पर पहले आयुर्वेद के डाक्टर रखे जाते थे। उसमें से उन लोगों को अब रखना बंद कर दिया है । वह तो मेरी खुद की जानकारी, है, विधायक के नाते जब में था उस विधान सभा में, तो कई लोगों को निकाला गया था।

आप कहते हैं कि आपने गाईडलाइंस दी हैं। हम यह चाहते हैं कि इसकी रिसर्च ज्यादा, अच्छे ढंग से करने के लिए इस पर ज्यादा जोर देने के लिए तथा साथ ही साथ जो गाईडलाइंस दी है तीसरे चिकित्सक के लिए, तो इस तीसरे आदमी को भारतीय पद्धति का ही होगा, इसको इम्पलिमेंट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

SHRI KRISHNA KUMAR: We have already sated that we are pursuing with the State Governments to implement the order. As regards the side-effects of allopathic drugs, the issue is governed by the Drugs and Cosmetics Act and the rules made thereunder. We agree with the honourable Member's proposition that the indigenous systems of medicine should be given the maximum encouragement by the Central Government and the States.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, इनको जवाब देना चाहिए कि यह इम्पलिमेंट नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 424.

*423. [*Transferred to the 20th December, 1985*].

Import of High Technology

*424. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Railways have currently formulated any plan to import high technology from Japan and other countries for improving high speed passenger trains. and existing railway Workshops, and maintenance and operation of freight; and

(b) if so, which are the major areas identified for high technology development to improve the technology used for maintaining the existing fleet of locos and coaches?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) The Indian Railways are planning to acquire technology for modern high speed coaches, freight car bogies. upgradation and modernisation of Production Units and Railway workshops and modernisation of signalling and telecommunication. Acquisition of high technology for this purpose from advanced countries including Japan is under consideration.

श्री धूलेश्वर मीणा: सभापति महोदय, हमारा देश अनेक कामों के लिए हाई टेक्नालाजी प्राप्त कर रहा है और जापान के अलावा दूसरे देश भी हमें हाई टेक्नोलाजी देने के लिये तैयार हैं यह हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जापान के अलावा वह कौन-कौन देश हैं कि जो हम को यह टेक्नालाजी देने के लिये तैयार हैं?

दूसरी बात हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी जून में यू एस ए गये थे तो उन को डिफेंस के दो आफिशियल्स मिले थे और इस बारे में कुछ बात हुई थी हाई टेक्नालाजी के बारे में कुछ बात हुई थी। तो मैं जानना चहता हूं कि इस बारे में क्या बात हुई थी और उस का क्या नतीजा रहा?

श्री माधवराव सिंधिया: कई देशों ने दिलचस्पी दिखायी है हमारी टेक्नालाजी को आधुनिक रूप देने में, हमें सहयोग देने में। पर अभी कोचेज और बोगीज के लिये हम ने ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किये हैं। उस के बाद जब इन पर कुछ रेस्पांस होगा उस के बाद ही पता चलेगा कि किस के साथ हमारे संबंध जुड़ते हैं टेक्नालाजी के माडर्नाइजेशन में और फिलहाल 18 लोकोमोटिव्ज के लिये आर्डर पेश किया गया है 6000 हार्स पावर के और जापान की एक कंपनी हिटाची को और स्वीडन की एक कंपनी आसिया को यह आर्डर प्लेस किये गये हैं।

आप के प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी ले कर मैं माननीय सदस्य को इत्तला कर दूंगा।

श्री धूलेश्वर मीणा: मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप ने फरमाया है कि:

"The Indian Railways are planning to acquire technology for modern high speed coaches, freight car bogies, upgradation and modernisation of production units.."

इस में प्लानिंग के बारे में कहा है। जो प्लान आप कर रहे हैं वह कब तक फाइनलाइज हो जायगा? और मेरा दूसरा सवाल है कि इस के बारे में जवाब नहीं दिया गया है कि: which are the major areas identified for high technology development to improve the technology used for maintaining the existing fleet of locos? इस के बारे में क्या कहना है आप को?

श्री माधव राव सिंधिया: जैसा कि मैंने कहा, अभी दो ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किये गये हैं और वे टेंडर्स जब खोले जायेंगे तभी निर्णय लिया जायगा कि किस देश के साथ कोलाबरेशन करना है, टेक्नालाजी के लिये एग्रीमेंट करना है। और जो जो क्षेत्र, आइडेंटिफाई किये गये हैं इस सहयोग के लिये, जैसा कि मैंने कहा पहले ही, नयी बोगीज के माडर्नाइजेशन के लिये और कोचेज के लिये और लोकोमोटिव्ज के फ्यूल एफीशियेन्ट इंजन्स के लिये और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिये, यह क्षेत्र हैं जो हम ने आइडेंटिफाई किये हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: सभापति जी, तेज गति की ट्रेन्स की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो रेल को तेज बनाया था उस की भी स्पीड को अब कम किया है। इस का आधार जब तक नहीं सुधारा जायेगा तब तक यह काम नहीं होगा। जैसे जब तक काठ की स्लीपर्स हैं उन को बदल कर कांक्रीट की स्लीपर्स को नहीं डाला जायगा और फिश प्लेट से जो नींद

डिस्टर्ब होती है उस को नहीं सुधारा जायगा तब तक मैं नहीं समझता कि विदेशों से तेज रफ्तार की गाड़ी चलाने की कोई योजना ठीक बैठ सकेगी। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि तेज गाड़ी के लिये क्या आप कांक्रीट स्लीपर्स को बदलने और फिश प्लेट को ठीक करने की बात सोच रहे हैं? दूसरे यह कि जब तक डबल लाइन नहीं हो जाती तब तक आप कैसे स्पीड बढ़ायेंगे। तीसरा खंड यह है कि जब तक कोयल के इंजनों की जगह पर बिजली या डीजल के इंजनों का प्रयोग नहीं कर लेते हैं तब तक तेज गति से ग्लोबल टेंडर लेने की बात आप कैसे करेंगे, इसकी जानकारी अगर मंत्री जी दे सकें तो कृपा होगी।

श्री माधव राव सिंधिया : श्रीमन इसी जानकारी के लिए हम सहयोग के समझौते करना चाहते हैं। जिन जिन विषयों पर अभी आपने प्रकाश डाला है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इसमें तरक्की की अभी बहुत गुंजायस है। इसीलिए हम हाई टेक्नालाजी की दूसरे देशों से चर्चा कर रहे हैं।

Magnetic Hovertrains

*425. SHRI KAPIL VERMA: †
DR. LOKESH CHANDRA: ,

Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to introduce magnetic hovertrains which glide 15 millimetres over a concrete track, on the pattern of the Transrapid Train in the Federal Republic of Germany which glides between the towns of Lather and Dorpen?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): No, Sir.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma.

SHRI KAPIL VERMA: The Prime Minister has been very rightly stressing the need for proper preparation to take the country into the 21st century. In a country of long distances and noted for population explosion transport will become increasingly difficult in the coming years and we will have to think of the most modern technology and underground and overground transport to solve the problem like the magnetic hovertrains introduced by West Germany, which glide 15 millimetres over a concrete track at a speed of 400 kms per hour with energy consumption many times lower than the present systems. The Transrapid Train links Cologne, Brussels and Paris. What I want to know from the Government is whether it is thinking of any perspective planning to overcome the transport problems that will arise in the coming years, whether any committee or working group has been set up to formulate concrete ideas for perspective planning and also whether the Government will consider introducing the magnetic hovertrains or some other modern technology.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: There is no information available with us regarding the commercial use of this magnetic hovertrain. The Member perhaps has more information on it. The Railway Board has no information as yet. As far as the information that we have goes, it is still on an experimental basis. In regard to the second part of his question where he has asked about the future planning for high speed trains, it is a very wide question. There is going to be a debate on the Supplementary Grants and I think we will cover this point at that time.

SHRI KAPIL VERMA: I have sent the relevant papers to the Minister and I hope he will look into them. My second supplementary is that the road transport in our national capital, Delhi, is becoming increasingly difficult and complicated everyday.